departmental action has been initiated against the delinquent engineers.

(c) Yes, Sir. An amount of Rs. 7, 68, 000/- (approximately) is alleged to have been over-paid in 3 cases.

(d) After completion of preliminary investigation into one case the Chief Vigilance Commissioner has advised for major penalty proceedings against the concerned Superintending Engineer and minor penalty proceedings against the concerned Surveyor of works. In addition, action against the contractor for recovery of alleged over-payments has also been initiated.

Smuggling of Boys and Girls from Bangladesh

1565. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that young boys and girls are smuggled into India from Bangladesh border for immoral purposes; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) The Government is aware that young women/girls are being smuggled into India across the Indo-Bangladesh border. However, no such case of smuggling of boys has come in notice.

(b) During the year 1989, three such cases involving 25 women/ girls were detected.

During the year 1990 (upto 15-5-90) one such case was detected involving six women/girls.

All the four cases have been registered with the local Police.

देश में बाई-पासों के लिए स्वीकृति देने में विलम्ब

1566. **श्री अजीत जोगी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर में बाई-पास के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के लिये मध्य प्रदेश के मुख्य अभियन्ता ने दिनांक 26 अगस्त, 1989 के अपने पत्र सं० 1110/एम-एच /आर०/89 द्वारा 3864 करोड़ रुपये का प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ;

(ग) बड़े शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई पास के निर्माण की स्वीकृति देने के लिये सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाये जाते हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि छोटे शहरों के लिये, जहां दुर्घटनाओं की संख्या नगण्य होती है, आसानी से स्वीकृति दे दी जाती है जबकि बड़े शहरों के लिये, जहां प्राय: प्रतिदिन लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नी कृष्णन) :(क) और (ख) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश ने इंदौर के चारों ओर बाई पास के निर्माण के लिये 38.64 करोड़ रु. का प्राक्कलन भेज है। राष्ट्रीय राजमार्ग–3 पर इंदौर सिटी के चारों ओर 42.45 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 31.4 कि०मी० लम्बे प्रस्ताव बाई पास के प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिये विश्व बैंक के समक्ष रखा गया है । विश्व बैंक को अभी अंतिम निर्णय लेना है । अत: अभी परियोजना को